

रुस

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मैंने घर छोड़ा
ओढ़ा देश निकाला

जाने किसकी तलाश में अलग जगाया
विराने छानी जंगल-जंगल भटका
पागलपन मुझपर भीड़ड़ राहों का था
इस पागलपन के क्या थे जाने-माने
सब समझे मैं हूँ नये गगन का पाखी
सब समझे मैं कुछ नया ढूँढ़ कर लाया
सच तो यह है मैं आज बता दूँ सबको
मैं पैँख पसार उड़ा जितनी दूर तक
वो सारा क्षितिज तुम्हारी बाँहों का था
इन होठों से जितना जो कुछ रस पाया, उसको ही
अपना गीत बनाकर गया
अब शाम उतर आई है
पथ धुंधलाया धीरे-धीरे उदास अधियारा छाया
राहें पगडंडी सब होती जाती गुम
अब मेरे और करीब, और करीब चलो तुम
जिस मन की मधुराई, तन की उजराई
मुझ को सम्भालकर इस मुकाम तक लाई
वो कदम-कदम गढ़ती उजयार चलेगी
ये यात्रा जन्म-जन्म के पार चलेगी।

- धर्मवीर भारती

उज्जयिनी में विक्रमोत्सव



उज्जैन से डॉ. जफर महमूद

भगवान शिव पशुपति हैं उनके अनेक स्वरूप हैं। शास्त्रों में शिवतत्व का विवेचन विस्तृत से किया गया है। जो शाश्वत, विशुद्ध शीघ्र कल्याण करने वाले हैं , वह शिव हैं। शैव परंपरा में वास्तुशास्त्रीय तत्व सदैव गवेषणा का विषय रहा है। भगवान शिव का स्वरूप और उनके अस्त्र डमरू, त्रिशूल आदि वास्तुशास्त्र और कल्याण के प्रतीक हैं।

ये विचार विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 'शैव परम्परा एवं वास्तु विज्ञान'विषय पर आधारित दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (काठमांडू) के प्रो. काशीनाथ न्यौपाने ने कही। संगोष्ठी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ तथा वास्तु विभाग, महीर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गयी। मुख्य अतिथि प्रो. न्यौपाने ने सम्राट

प्रसंगवश

रजनीश कुमार

रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने उस सुझाव पर सहमति दे दी है, जिसमें रूस और अमेरिका सैन्य बजट में बड़ी कटौती पर बात कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य बजट में 50 फ़ीसदी तक की कटौती पर बात हो रही है।

पुतिन ने कहा था, 'हम अमेरिका के साथ सैन्य खर्चों में कटौती को लेकर एक समझौते पर पहुँच सकते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। यह ऐसा सुझाव है, जिससे मैं भी सहमत हूँ। अमेरिका अपने सैन्य बजट में 50 फ़ीसदी की कटौती करेगा और हम भी वैसा ही करेंगे। चीन भी चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है।' लेकिन चीन को पुतिन का यह सुझाव पसंद नहीं आया।

25 फरवरी को समाचार एजेंसी एएफ़पी ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जिआन से पूछा कि पुतिन ने कहा है कि चीन भी इस प्रस्ताव में शामिल हो सकता है, क्या चीन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा? 24 फरवरी की रात राष्ट्रपति शी जिनिपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें क्या इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी?

इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिन जिआन ने कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनिपिंग के बीच फोन पर जो बातचीत हुई, उसका रीडआउट जारी किया जा चुका है। आपने रक्षा खर्चों की बात की। हाल के वर्षों में वैश्विक रक्षा खर्चों में भारी बढ़ोतरी हुई है।' 'ऑकड़ों के मुताबिक 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च 2.43 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड

है। वैश्विक रक्षा खर्चों में भारी बढ़ोतरी बढ़ती वैश्विक असुरक्षा के कारण है। सभी देश वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को और खास कर बड़े देशों को विश्व शांति के लिए पहल करनी चाहिए।'

लिन जिआन ने कहा, चीन शांतिपूर्ण प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, विकास से जुड़े हित और विश्व शांति बनाए रखने को रक्षा खर्चों को सीमित करने से जोड़ना उचित नहीं है। चीन की अपनी आत्मरक्षा रणनीति है, जिसके तहत हम राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय बनाते हैं। चीन किसी भी देश से हथियारों की होड़ नहीं कर रहा है। हमारी नीति दुनिया की स्थिरता और शांति के पक्ष में है। चीन ने पुतिन के प्रस्ताव को स्वीकार तो नहीं किया लेकिन कुछ अहम बातें कहीं।

चीन ने कहा कि हाल के वर्षों में रक्षा खर्च दुनिया के कई इलाकों में तनाव के कारण बढ़ा है। चीन ने यह भी कहा कि बड़े देशों की ज़िम्मेदारी है कि शांति के लिए काम करें।

लिन से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका का सैन्य खर्च दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है और उसे मिसाल पेश करना चाहिए।

चीन ने कहा था कि दुनिया के 90 प्रतिशत परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। ऐसे में पहले इन्हें अपना परमाणु हथियार कम करना चाहिए तब बाक़ी देशों से कहना चाहिए।

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफ़ेसर

डॉ. राजन कुमार मानते हैं कि रक्षा खर्चों में कटौती के लिए पुतिन का तैयार होना बहुत हुरान नहीं करता है। हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच समझौते होते रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि वह अमेरिका के साथ हथियारों में होड़ कर सकता है। अब असली होड़ चीन और अमेरिका के बीच है लेकिन चीन ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेगा। चीन को लगता है कि वह अब भी सैन्य ताक़त के मामले में अमेरिका से पीछे है और जब तक अमेरिका की बराबरी नहीं कर लेगा तब तक रक्षा बजट में कटौती के लिए तैयार नहीं होगा। रूस यह भी नहीं चाहता है कि चीन सैन्य ताक़त के रूप में महाशक्तिशाली बन जाए। चीन रूस का पड़ोसी है।

1969 में आमूर और उसुरी नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका है। इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। इसमें चीन को क़दम पीछे खींचने पड़े थे। 2004 में दोनों देशों के बीच समझौते हुए और सेंट्रल एशिया के कई द्वीपों को रूस ने चीन को सौंप दिया था।

यूक्रेन और रूस की जंग में चीन आधिकारिक रूप से तटस्थ रहा है लेकिन इस दौरान रूस से गैस और तेल सबसे ज़्यादा चीन ने ही आयात किया है। यूरोप का कहना है कि रूस-यूक्रेन जंग के दौरान पुतिन को चीन से काफी मदद मिली है।

लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फ़ोर स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ (आईआईएसएस) ने 12 फरवरी को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल वैश्विक सैन्य खर्च 2.46 ट्रिलियन डॉलर

तक पहुँच गया था। 2024 में चीन का सैन्य खर्च 236 अरब डॉलर था। चीन ने 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि चीन का असली सैन्य खर्च आधिकारिक ऑकड़ों से कहीं ज़्यादा होता है। हाल के दशकों में चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का तेज़ी से आधुनिकीकरण किया है। शी जिनिपिंग का लक्ष्य है कि जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का 2049 में 100 साल हो जाए तो एक वर्ल्ड क्लास आर्मी तैयार हो जानी चाहिए।

चीन की इसी तैयारी को अमेरिका चुनौती के रूप में देखता है। चीन की बढ़ती ताक़त से भारत, जापान और ताइवान भी चिंतित हैं। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है।

अमेरिका और रूस की बढ़ती क़रीबी पर दुनिया भर की नज़रें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भरोसा किस हद तक बढ़ता है, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद रूस और चीन में गर्मजोशी बढ़ी थी। पश्चिम के कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस के पास चीन के क़रीब जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन ट्रंप अब रूस को लेकर जिस तरह की उदारता दिखा रहे हैं, उससे पूरा समीकरण बदलता दिख रहा है।

ट्रंप का कहना है कि जब यूक्रेन की समस्या सुलझ जाएगी तब रक्षा खर्चों और परमाणु हथियारों को कम करने पर बात शुरू होगी। ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सूप्रीम कोर्ट का अदालतों को निर्देश, खींच दी न्यायिक समीक्षा की लक्ष्मण रेखा

यूएपीए में गिरफ्तारी की समीक्षा



उत्तराखंड में टूटा बर्फ का पहाड़

फंसीं 41 ज़िंदगी

16 लोगों को निकाला, सड़क से बर्फ हटाने गए थे

वास्तु सिद्धान्तों के उदाहरण हैं शैव परम्परा के देवालय



प्रो. विजयकुमार सी.जी. ने भारतीय संस्कृति में शैव आगम और इस दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा में कहा कि शिव ही जगत का मूल चेतन तत्व हैं ,जो बंधन तथा मुक्ति का कारण हैं। उन्होंने मंत्र वास्तु, शैवमत, शिव की शाश्वत सत्ता और अनेक दर्शन और मतों को प्रस्तुत करते हुए विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की बधाई दी। अर्थाति परिचय डॉ. तुलसीदास परौह ने दिया विषय प्रवर्तन संयोजक डॉ. शुभम शर्मा ने प्रस्तुत किया। आभार कुलसचिव प्रो. दिलीप सोनी ने माना। संचालन डॉ. विजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में नेपाल, म्यांमार तथा वियतनाम के शिक्षाविद् सहित भारत के विभिन्न भागों के विद्वान, छात्र तथा शोधार्थी उपस्थित थे।

आदि-अनादि पर्व- डमरू वादन के साथ मलखम्ब का प्रदर्शन

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा उज्जयिनी विक्रम व्यापार मेला मंच पर मुकेश शास्त्री द्वारा डमरू वादन और योगेश मालवीय के निदेशन में मलखम्ब का प्रदर्शन किया गया। मखकाल कांछिडोर के ओपन मंच पर अतिशो तिवारी एवं सांथियों द्वारा शिव केन्द्रित भक्ति गायन प्रस्तुत किया गया।

भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में गढ़े हैं नए कीर्तिमान : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री द्वारा विज्ञान आधारित कार्यप्रणाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति और नवीनतम तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन से देश को मिली उपलब्धि



सम्मानित महान वैज्ञानिक श्री सीवी रमन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 'सेंटर ऑफ़ एक्सिलेंस इन स्टेम एजुकेशन' का विज्ञान भवन में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सींटर में प्रस्तुत मॉडल तथा विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न

सरकार शिक्षा सहित शासकीय कार्य प्रणाली और सामान्य व्यवस्थाओं के संचालन में विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग कर आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने' की थीम पर भोपाल में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्वलित कर तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पूर्व उन्होंने नोबल पुरस्कार से

सिद्धांत, सरलता से समझाने में सहायक उपकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल और नवाचारों के संबंध में उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीकमगढ़ से आए प्रतिनिशील कृषक श्री पूरनलाल कुशवाहा से भेंट कर उनके द्वारा सिंचाई के लिए विकसित किए गए पवन और पानी से चलने वाले पंप का अवलोकन कर जानकारी भी प्राप्त की।



























पुणे में सरकारी बस में रेप केस का आरोपी अरेस्ट

गन्ने के खेत में छिपा था, पानी पीने गांव में आया, लोगों ने पुलिस को खबर कर दी



उसे पहचान लिया और जानकारी पुलिस को दे दी। आरोपी को पकड़ने में भी लोगों ने मदद की। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा- आरोपी बीती रात 1.10 बजे गुनात गांव से पकड़ा गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक स्पेशल वकील नियुक्त किया जाएगा। हम केस को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे की जांच के लिए आरोपी को पुणे भेज दिया गया है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे ने 25 फरवरी को सरकारी स्वारगेट डिपो में इस वारदात को अंजाम दिया था। उस पर 1 लाख रुपए का ईनाम था।

संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका



प्रयागराज (एजेंसी)। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने शुक्रवार सुबह अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा- मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ-सफाई कराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया। हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। दरअसल, 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर अस्गर ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था- हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी।

मणिपुर में फिर भड़के कुकी संगठन, दे दी वॉर्निंग

कहा-इंफाल के लिए घातक हो सकती है अरमबाई टेंगूल से बातचीत



वहीं राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गवर्नर अजय भल्ला ने उग्रवादियों से लुटे गए हथियारों को सरेंड़ करने की तारीख दे दी थी। इसके बाद बड़ा हथियारों का जखीरा सुरक्षाबलों और पुलिस के पास वापस आ गया है। मणिपुर में अरमबाई टेंगोल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को इंफाल में प्रथम मणिपुर राइफल परिसर में कुल 307 हथियारों में से 246 हथियार सौंपे, जबकि पहाड़ी और घाटी जिलों में अन्य स्थानों पर 61 और हथियार सौंपे गए। पुलिस ने बताया कि अरमबाई टेंगोल के सदस्यों ने आज मणिपुर सरकार के सामने हथियार सौंपे। पुलिस ने बताया कि अरमबाई टेंगोल का राज्यपाल करना इंफाल की जनता के साथ अन्याय है। वे खुद मिलकर अपनी समस्याएं रखना चाहते थे लेकिन बीच में टेंगोल ने दखल दे दिया। अब यह इंफाल के लिए घातक हो सकता है।

अब सिद्धारमैया ने अमित शाह से मांग ली एक गारंटी

परिसीमन विवाद: कहा-दक्षिण भारत के 5 राज्यों का डर तभी खत्म होगा





बेंगलुरु (एजेंसी)। लोकसभा सीटों का परिसीमन होने के बाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसे लेकर राजनीति तेज है और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने तो राज्य के सभी दलों की मीटिंग बुलाई है। यही नहीं अब यह मसला जोर पकड़ता जा रहा है और कर्नाटक के सीएम एम. सिद्धारमैया ने भी इसे लेकर केंद्र से गारंटी मांगी है। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह की उस बात को लेकर भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु या फिर दक्षिण के किसी अन्य राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। सिद्धारमैया ने कहा कि यदि 1971 की जनगणना के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि होम मिनिस्टर अमित शाह कहें कि 1971 के आंकड़ों का ही प्रयोग किया जाएगा तो माना जा सकता है कि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं होगा। दरअसल एमके स्टालिन की ओर से जाहिर की गई चिंताओं पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को सीटों का नुकसान नहीं होगा। एमके स्टालिन की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी यह जोर पकड़ रहा है। दरअसल ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उत्तर में सीटें बहुत ज्यादा होंगी।

देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में फैला बर्ड फ्लू

● एमपी के छिंदवाड़ा से लिए सैपल की रिपोर्ट पॉजीटिव

● मटन-चिकन और अंडे की खरीदी-बिक्री पर लगी रोक



पालतू बिल्लियों के सैपल एच5एन1 (बर्ड फ्लू) पॉजीटिव मिले थे। देश में ऐसा पहली बार है, जब घरेलू बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस पक्षवार ने बताया कि मृत बिल्लियों को कच्चा मांस जिन दुकानों से खिलया गया था, उन 2 दुकानों विक्की चिकन सेंटर और नावेल्टी सेंटर के यहां सैपलिंग की गई, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। प्रभावित क्षेत्र में प्रोटोकॉल का पालन कर संबंधित क्षेत्र में मटन, मुर्गी और अंडों को नष्ट किया गया। साथ ही मार्केट में इनके क्रय विक्रय पर पाबंदी लगा दी गई थी।

तेलंगाना टनल हादसा

अंदर फंसे मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम



रेलवे की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी, 22 फरवरी से 8 मजदूर फंसे हैं

नागरकुर्नूल (एजेंसी)। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन टनल में फंसे 8 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू जारी है। शुक्रवार को साउथ सेंट्रल रेलवे की 2 टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंचीं। टीम भारी धातुओं को प्लाज्मा कटर और ब्रॉक कटिंग मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों से काटने रास्ते से हटा रही है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंचे हैं। ग्राउंड पेनेट्रेंटिंग रडार की मदद से मलबे में दबे मजदूरों ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी मजदूर के जीवित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। नागरकुर्नूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मलबा हटाने और लोहे की छड़ों की कटिंग का काम लगातार जारी है। टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है।

अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं, मोहल्ला क्लीनिक से शौचालय भी मिले गायब

कैंग रिपोर्ट में दिखी दिल्ली की ‘आपदा’, कई जगह एंबुलेंस भी नदारद



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा कैंग रिपोर्ट की हो रही है, रेखा सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान कुल 14 फाइलें पेश की गई हैं। वहां भी राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई हेरान कर देने वाले दावे हुए हैं। कैंग की रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे, एंबुलेंस की संख्या भी काफी कम, इसके ऊपर मोहल्ला क्लीनिक में शौचालय गायब रहे। कैंग रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 14 ऐसे अस्पताल हैं जहां अभी तक आईसीयू बेड नहीं हैं, 12 ऐसे अस्पताल सामने आए हैं जहां एंबुलेंस की कोई सुविधा नहीं। इसके ऊपर कई ऐसे मोहल्ला क्लीनिक पाए गए जहां कोई शौचालय ही नहीं है। भारत सरकार से कोविड के दौरान जो फंड मिले थे, उसे लेकर भी कैंग ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उस पैसे को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया। वो आंकड़े पाएंगी, यानी कि काफी पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यह मायने इसलिए रखता है क्योंकि दिल्ली में कोरोना का दूसरा लहर के दौरान काफी तबाही देखने को मिली थी।

जन्म से हिंदू हूं, इसलिए महाशिवरात्रि कार्यक्रम में गया

● कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बोले-अमित शाह भी थे शामिल ● कांग्रेस सचिव बोले- डिप्टी सीएम राहुल का मजाक उड़ाते वालों के साथ



चेन्नई (एजेंसी)। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 26 फरवरी को ईशा फाउंडेशन की तरफ से कोयंबटूर में आयोजित महाशिवरात्रि कार्यक्रम में गए थे। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पीवी मोहन ने शिवकुमार की कोयंबटूर यात्रा पर निशाना साधा। पीवी मोहन ने सोशल मीडिया पर लिखा- शिवकुमार एक ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर गए, जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। पीवी मोहन के आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा- मैं एक हिंदू हूं। मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं और मैं एक हिंदू के रूप में मर जाऊंगा, लेकिन मैं सभी धर्मों से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। शिवकुमार बोले- सद्गुरु जगगी वासुदेव एक महान इंसान हैं शिवकुमार ने सद्गुरु के कार्यक्रम में जाने को लेकर कहा कि ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु जगगी वासुदेव आए



और मुझे (कोयंबटूर में शिवरात्रि समारोह के लिए) आमंत्रित किया। वे मैसूर से हैं। वे महान व्यक्ति हैं और मैं उनके ज्ञान और कद की प्रशंसा करता हूं, लेकिन कई लोग उनकी आलोचना करते हैं। योगी सरकार का कुंभ का आयोजन सराहनीय: महाकुंभ के बारे में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से उन्होंने (योगी सरकार) इसे आयोजित किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। यह कोई छोटा काम नहीं है। यहां-वहां कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ट्रेनों के कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे खासियां निकालना पसंद नहीं है। यह बहुत संतोषजनक है। भाजपा से किसी तरह की साठगांठ नहीं: भाजपा के साथ साठगांठ के आरोपों का जवाब देते हुए शिवकुमार ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में सभी को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है। महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी यही किया।

संपादकीय

महाकुंभ : अब सियासी लाभ के दावे

विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर समापन हो गया। इस महाकुंभ में सरकारी दावे के मुताबिक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के समय मची भगदड़ में 37 श्रद्धालुओं की मौत और आगजनी की आधा दर्जन दामदार घटनाओं को छोड़ दें तो इस महाविराट आयोजन की व्यवस्था को मोटे तौर पर सभी ने सराहा। अमीर गरीब, ऊंची नीची जातियों और हिंदुओं के अलावा बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोगों ने भी अपनी श्रद्धा के मुताबिक संगम में स्नान कर पुण्य कमाया। इस महाकुंभ की विशेषता यह रही कि इसमें तमाम इंतजाम और श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ तो थी ही, साथ में इसे धार्मिक पर्यटन, आर्थिक प्रबंधन और परीक्ष रूप से राजनीतिक निवेश का रूप भी बहुत सुनियोजित तरीके से दिया गया था। यही कारण है महाकुंभ की सफलता के बाद उजाव से भाजपा साक्षी महाराज ने कहा कि महाकुंभ की सफलता ने यह कर दिया है कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी। इसका सीधा अर्थ यही है कि अगर अभी चुनाव हुए तो भाजपा बंपर वोटों से जीतेगी। मसलन संगम में डुबकी लगाने वाले सभी 66 करोड़हिंदू भाजपा के वोटर हुए तो यह संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश भर में मिले कुल 23 करोड़ वोटों से भी दोगुनी होगी। लेकिन यह कागजी गणित है और कुंभ में स्नान करने वाला हर व्यक्ति भाजपा का ही वोटर हो, यह जरूरी नहीं है। यानी कि हरेक की धार्मिक और राजनीतिक आस्था एक सी हो ये जरूरी नहीं है। और राज्यों के मामले में यह प्रकरण और भी अलग हो जाता है। महाकुंभ का भाजपा को कितना लाभ मिलेगा, मिलेगा या नहीं इस प्रश्न को अलग रखें तो भी योगी सरकार ने जिस बड़े पैमाने पर इंतजाम किए और इस में लोगों ने जिस तरह दिन रात मेहनत कर महाकुंभ को सफल बनाने में जी जान लगी है। उनकी सराहना अवश्य की जानी चाहिए। इसी तरह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने विभाग के कर्मचारियों की कुंभ में दी गई उनकी सेवाओं की तारीफ की। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाकुंभ की लगातार मॉनिटरिंग की। हालांकि इस समागम के समापन पर उन्होंने महाकुंभ के आलोचकों को बुरे शब्दों में लताड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि महाकुंभ कहीं कोई अव्यवस्था थी ही नहीं। जो थी, उस पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ी। अपनी तकलीफों को लोगों ने पुण्य लाभ की अपेक्षा में अनदेखा किया। महाकुंभ के अंत योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस ढंग से कुंभ के सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया, उन्हें बोसस घोषित किया, सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कृत किया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। चंद खामियों के बावजूद इतना महाविराट आयोजन करना भी अपने आप में उल्लब्धि है। यह विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। यही कारण है कि सनातनियों के इस महापर्व का सारी दुनिया ने सुखद आश्चर्य के साथ नोटिस लिया। इस मायने में यह महाकुंभ भविष्य में दलैतारी की और पुखा किया है। अगर योगी यूपी में तीसरी बार भाजपा को सत्ता में लौटा लाते हैं तो तय मानिए कि मोदी के बाद वो भाजपा व संघ की पहली पसंद होंगे। अब यह यूपी की जनता पर निर्भर है कि वो तीसरी बार योगी को सत्ता सौंपती है या नहीं।

पर्यावरण

डॉ. ललित कुमार

लेखक इन्वॉर्जन विश्वविद्यालय बरेली में पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं।



यूनेस्को ने वर्ष 2011 में विश्व रेडियो दिवस को हर वर्ष 13 फरवरी को मनाने की घोषणा की। तब से लेकर आज तक फरवरी की 13 तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाने की परंपरा बर गई है। देशभर के पत्रकारिता विभाग में मीडिया की पछाई कर रहे युवा पीढ़ी ने शायद ही इस श्रव्य माध्यम को कभी सुना हो। अमूमन रेडियो सुनने वालों की तादाद पिछले कुछ वर्षों में गिरावट देखी गई है, जोकि एक चिंता का विषय हो सकती है। आजादी के बाद से रेडियो को तीव्र गति वाला एक सशक्त माध्यम माना जाता था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो को सबसे ज्यादा सुनने वाला माध्यम माना गया। रेडियो ने ग्रामीण व शहरी समाज के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। क्योंकि यह सभी वर्गों को समान रूप से सूचना देने का काम करता है।

रेडियो जहां तीन फॉर्मेट पर काम करने वाला माध्यम माना जाता है। जिनमे क्रमशः बोले जाने वाला शब्द या मानव ध्वनि, संगीत और ध्वनि प्रभाव के रूप में जनता के दिलों की धड़कन बना। रेडियो हमेशा संचार का एक ऐसा माध्यम रहा, जिसने कभी किसी धर्म संप्रदाय के खलिफा या सूचनाओं के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि सूचना को हर वर्गों के बीच बड़ी शालनीनता के साथ प्रसारित किया। रेडियो ने देश के विकास में सूचनाओं की सीमा को समझा और सभी के साथ न्याय किया। किसी भी वर्ग को निराश न करने वाला यह माध्यम आज भी इतना प्रासंगिक है कि इसकी पहचान और इसके श्रोता रेडियो को सम्मान के साथ ही सुनना पसंद करते हैं।

वर्ष 2025 की थीम ‘रेडियो और जलवायु परिवर्तन’ को लेकर रखी गई। जहां आज हर देश और हर समुदाय को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो ने फिर से यह पहल की है। प्राकृतिक आपदाओं आपातकालीन समय या कर्ष्यू के समय सबसे सशक्त माध्यमों में से एक रहा है। रेडियो श्रोता इतना तो समझ ही सकते हैं कि रेडियो की आवाज

नजरिया

अशोक भाटिया

लेखक मुंबई निवासी स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।



बांग्लादेश पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। शेख हसीना की सरकार चली गई थी। उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा।

फिर अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनूस पर आ गई। लेकिन एक बार फिर, देश में हिंसा भड़क उठी है। शेख हसीना के शासन के अंत को एक साल भी नहीं हुआ है। वहीं, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ छत्र सड़कों पर उतर आए हैं। ये था। छत्र आंदोलन का नेतृत्व शेख हसीना की सरकार के दौरान छत्र नेता नाहिद इस्लाम ने किया था। इस आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई। अब छत्र एक बार फिर यूनूस के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं।

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है, जिसमें नाहिद इस्लाम को एडवाइजरी का पद दिया गया था; लेकिन अब उन्होंने सलाहकार के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। शेख हसीना की सरकार के दौरान भेदभाव विरोधी आंदोलन और हिंसक छत्र आंदोलन हुए थे। वह हसीना सरकार के पतन के मुख्य कारणों में से एक थे। छत्र आंदोलन का नेतृत्व छत्र नेता नाहिद इस्लाम ने किया था। कार्यवाहक के रूप में पद छोड़ने के नाहिद इस्लाम के फैसले ने बांग्लादेश में यूनूस सरकार की स्थिरता के बारे में संदेह पैदा कर दिया है और अटकलें लगाई हैं कि यूनूस सरकार जल्द ही कभी भी गिर जाएगी।खबर यह भी है कि वह नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं और जल्द इसका ऐलान हो सकता है।

बीडीन्यूज़ डॉट 24 की रिपोर्ट के मुताबिक, नाहिद इस्लाम और सरजिस आलम इस नए दल की अगुवाई कर सकते हैं। सरजिस स्टूडेंट ऑर्गेस्ट डिस्क्रीमिनेशन के कॉर्डिनेटर हैं। बता दें कि नाहिद इस्लाम की अगुवाई वाले छत्र आंदोलनों के बीच पिछले साल पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी। इसके बाद आठ अगस्त को मोहम्मद यूनूस की अगुवाई में नई अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था।

अब अगर हम बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम को देखें तो छत्र यूनूस सरकार के कुछ फैसलों से नाखुश हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर, 31 दिसंबर की शाम

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनूस सरकार में उथल-पुथल

को, हजारों छत्र ढाका में केंद्रीय शाहिर मीनार के पास इकट्ठा हुए और वर्तमान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। छत्र संघ बांग्लादेश के निर्माण के समय 1972 में लागू संविधान को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। छत्र संघ ने भारत के संविधान को मुजीबिस्ट संविधान के रूप में वर्णित किया है। छत्रों का आरोप है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत और बांग्लादेश, जिनके कभी दोस्ताना संबंध थे, अब तनाव के बिंदु पर पहुंच गए हैं। भारत-बांग्लादेश संबंध चीन के साथ मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की निकटता के कारण बिगड़ते प्रतीत होते हैं। भारत ने



1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश को मान्यता दी। भारत और बांग्लादेश दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच निरंतर दोस्ती को मनाने के लिए फंडेशनप डे मनाया जाता है। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत थे; लेकिन उनके अपदस्थ होने के बाद, स्थिति बदल गई। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद भारत आई। मोहम्मद यूनूस की नीतियों ने भारत के साथ संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए, मोहम्मद यूनूस ने चीन की प्रशंसा की और संकट के समय में बांग्लादेश को चीन के समर्थन का उल्लेख किया।

इससे पहले बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार-उज्जमान ने सभी नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्हें आपस में नहीं उलझने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इससे देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। अगर लोग अपने मतभेदों ना भुला पाए या एक-दूसरे पर आरोप लगाना बंद ना कर पाए तो देश की संप्रभुता दांव पर लग सकती

है। उन्होंने मंगलवार को पिलखाना नरसंहार की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। बाद में यह मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। अगर आप अपने मतभेदों को भूलकर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो एक-दूसरे पर आरोप लगाने हैं तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने पुलिस बल की अक्षमता पर भी सवाल उठाए और बताया कि कई अधिकारी डर में जी रहे हैं, क्योंकि उनके साथी या तो जेल में हैं या उन पर मुकदमे चल रहे हैं।

सेना प्रमुख ने कहा कि देश की कानून एवं व्यवस्था



खराब होने के ये कुछ कारण हैं। पहला कारण है कि हम आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं। अगर आप अपने मतभेदों को नहीं भुलाते हैं तो इससे दिक्कत होगी। देश की संप्रभुता जोखिम में पड़ जाएगी। मैं चेतावनी दे रहा हूं। सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं जिससे शरारती तत्वों को माहौल बिगाड़ने में फायदा हो रहा है। इस अराजक स्थिति में वे आसानी से बच रहे हैं।

लोगों को एक बड़ी चिंता ये भी है कि यूनूस के जमात-ए-इस्लामी से अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। कम से कम उनके हालिया राजनैतिक फैसलों से यही झलकता है। अंतरिम सरकार के लीडर बतौर उन्होंने इस गुट पर लगी पाबंदियां हटा दीं। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी पर कट्टरपंथी राजनैतिक गुट है, जिसके खिलाफ खुद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए उसके चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी। पॉलिटिकल गतिविधियों के अलावा वो कोई सभा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंतरिम सरकार के आते ही उसपर से सारी रोकटोक खत्म हो गईं।

वैज्ञानिक चेतना और हमारा व्यवहार

अनुभव

अनिल धीमन

लेखक स्तंभकार हैं।

28

फरवरी को रमन दिवस मनाया गया। आज हम देखते हैं कि वैज्ञानिक सोच के मामले में हम आगे की जगह पीछे जा रहे हैं क्योंकि मामला वैज्ञानिक सोच-विचार के होने और उसको दैनिक व्यक्ति पेशे से वैज्ञानिक हो लेकिन उसके चेतन और व्यवहार में वैज्ञानिक सोच झलकनी चाहिए। आजादी के 74 साल बाद भी देश में एक वर्ग ऐसा है जिन्हें लगता है कि दुनिया को एक शक्ति संचालित कर रही है। बेशक हम जिस ब्रह्मांड के एक छोटे से सौर मंडल के एक तुच्छ ग्रह के प्राणी मात्र हैं और कुछ नहीं। जो कुछ भी हम है सब एक तारे के अंश है जिसे एक शक्ति कह सकते हैं क्योंकि हमारा सूरज ही सब कुछ है जो हमें ऊर्जा देता है। अगर ये सूरज कुछ बंटों के लिए बुझ जाए तो हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी और हम सब डायनासौर की तरह फॉसिल में तब्दील होने की प्रक्रिया कर दें जाएंगे। खैर, यह अनुमान है लेकिन उसके भी लिए 6 करोड़ वर्ष का समय लगेगा और यह तब होगा जब सूरज सुपरनोवा एक्सपोलोसन या रेड जॉईंट की स्थिति में आएगा यानी धरती का सबसे करीबी तारा हमारा सूरज मरने लगेगा। तारे जब मरते हैं तो उनका आकार कई लाख गुना बड़ा होता है। ठीक उस तरह जैसे बुझने के पहले दीये की लौ बढ़ जाती है। तारे इसी तरह मरते हैं।

1609 को वैज्ञानिक चिंतन का स्वर्ण युग माना जा सकता है। यूरोप का यह दौर चर्च की शक्ति के अधीन था। एक छोटा से साधारण सा यंत्र (टेलीस्कोप) का उपयोग करते हुए गैलीलियो गैलिली ने आकाश के कमकपे हुए पिंडों (ग्रहों) को खोज निकाला जो धरती की

तरह सूरज के चक्कर लगाते हैं। यह बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और इस पर बहसों का दौर शुरू हुआ। खुद एक धार्मिक गुरु (चर्च में पारी) होने के बावजूद गैलीलियो गैलिली ने पुरातन विचार को चुनौतियां दीं। इसके परिणामस्वरूप गैलीलियो को नजरबंद कर दिया और मरते दम तक रहना पड़ा। बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रह , शनि का वलय (रिंग) आज से 400 वर्ष पूर्व गैलीलियो ने एक छोटे से टेलीस्कोप से खोज लिया था। उस सच को आज भी आप आकाश में देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि एक धर्म का प्रचारक पाद्री होकर भी वैज्ञानिक सोच कि वजह से आज दुनिया को इस रूप में बदलने कि सोच को विकसित कर गया। हालांकि उससे पूर्व और उस दौर के भारतीय वैज्ञानिकों का भी खगोल विज्ञान कि व्याख्याएं और योगदान रहा है। 1734 देश में बने जंतरमंतर जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह कि वैज्ञानिक सोच का ही नतीजा है। जतरमंतर जयपुर के अलावा दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में स्थित हैं।

मेरा मानना है कि धार्मिक होना व्यक्तिगत मामला है। हमारा संविधान इस बात की स्वतंत्रता भी देता है कि आप किसी भी धर्म या भाषा को अपना सकते हैं। कथनी और करनी का अलग होना आपको वैज्ञानिक सोच से दूर करता है। हम सब जानते हैं अविष्कार करने के लिए संघर्ष होगा ही, कुतर्कों से भी गुजरना पड़ेगा। घर और विद्यालय के अंतर्द्वंद को वो बच्चा समझ नहीं पाता है। बच्चे को स्कूल में यह बताया जाता है कि एक खास समय में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के एक सीध में आने से सूर्य ग्रहण होता है। वो परीक्षा में जवाब भी यही लिखता है जो पढ़ाया गया है लेकिन मान्यताएं उसके दिमाग से राहु-केतु निकलने नहीं देती है। यह असर केवल बच्चों तक नहीं सीमित है। जो शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे हैं अधिकतर वे भी उलझे हुए हैं।

टूटी कुर्सी और लूटी व्यवस्था

से फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाया।

फोन की स्क्रीन पर चमकता था ‘भानेज कॉलिंग’। मामा और उनकी टूटी कुर्सी ‘नमस्ते मामा! कहीं हैं आप?’ दूसरी ओर से आवाज़ आई।

‘अरे भानेज, क्या बताऊँ! फ्लाइट में हूँ, और देखो, टूटी हुई सीट पर बैठाया है मुझे। बैठना मुश्किल हो रहा है!’ मामा ने शिकायत की, मानो देश का सबसे बड़ा संकट इसी समय उन पर टूट पड़ा हो।

भानेज की आवाज़ में चिंता झलकी ‘ओह! यह तो गंभीर बात है मामा! लेकिन आप चिंता न करें, विमान मंत्रालय मेरे अधीन है। मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा।’

मामा की पीड़ा कुछ इस तरह झलकी जैसे एक दिन की तकलीफ से पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन तभी पास बैठे एक बुजुर्ग यात्री मुस्कुराते हुए बोले, ‘मामा जी, कुर्सी टूटी है, लेकिन किसानों की टूटी उम्मीदों का क्या? उनकी समस्याएँ कौन सुलझाएगा?’ मामा थोड़ा असहज होकर ‘अरे भाईसाहब, किसानों के लिए बजट में बहुत कुछ हैज हवाई जहाज में चर्चा का क्या फायदा! लेकिन अभी बात एयरलाइन की

लापरवाही की है।’

इतने में पीछे से एक युवा यात्री हंसते हुए बोला, ‘वाह मामा! एक दिन की असुविधा से आप इतने परेशान हैं। लेकिन किसानों की दशकों से चली आ रही समस्याओं पर कब ध्यान देंगे?’

मामा के चेहरे पर हल्की परेशानी के बादल मंडराने लगे। वे कुछ कहते, इससे पहले ही भानेज ने गंभीर स्वर में कहा, ‘मामा, मैं समझता हूँ। एयर इंडिया की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’

अब तक संशय से सुन रहे थे, लेकिन तभी बगल वाले यात्री ने तंज कसते हुए कहा, ‘भानेज जी, एयर इंडिया आपके मंत्रालय के अधीन है। अपनी ही लापरवाही पर आप क्या कहेंगे?’

विमान में हल्की हंसी गूंज उठी। मामा असहज होकर सीट एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीट जस की तस थी। तभी एयर होस्टेस पास आई।

‘सर, हम आपकी सीट बदल सकते हैं।’ मामा ने सोचा, ‘अगर सीट बदल लूंगा तो जनता

को क्या संदेश जाएगा?’ इसलिए उन्होंने महानता का परिचय देते हुए कहा, ‘नहीं, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। मैं इसी सीट पर सफर करूंगा।’

अब तक यात्री भी मनोरंजन का पूरा लुत्फ उठा चुके थे। किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ‘मामा जी, किसानों की समस्याएँ भी समझिए, सिर्फ अपनी कुर्सी की नहीं।’

मामा चुप हो गए। भानेज भी कुछ नहीं बोल पाए। फ्लाइट लैंड हुई। मामा उठे, कैमरे की ओर देखा, और गंभीर मुद्रा में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे ‘यात्रियों की समस्याएँ हमारी प्राथमिकता हैं। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा।’

मुझे हंसी आ गई। मैंने बगल में बैठे यात्री से कहा, ‘टूटी कुर्सी तो बहाना था, असली निशाना तो भानेज पर था!’ यात्री मुस्कुराए और बोले, ‘और जनता? वह फिर से अपनी दैनिक समस्याओं में व्यस्त हो जाएगी।’

मैंने खिड़की से बाहर झांका जहाँ एक और ‘टूटी कुर्सी’ किसी नए नाटक का ईंटज्जर कर रही थी।

सुबह सवेरे मोडिया एल.पी.के

उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ़्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउडवेडी, देवास रोड,

इंदौर से मुद्रित्र एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

संपादक

उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)

RNI No. MP/PHIN/ 2015/ 66040,

Mobile No.: 09893032101

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

कलापक्ष

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो हैं।



जै | से-जैसे क्षेत्रीय नाट्य परम्पराएँ विकसित हुई हैं, भारत का रंगमंच और प्रदर्शन कलाएँ सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक रही हैं। न्याय को बढ़ावा देने, सत्ता का विरोध करने और सामाजिक अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रंगमंच एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। बढ़ते क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, राष्ट्र का प्रश्न और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की जटिल कथाओं ने क्षेत्रीय नाट्य परम्पराओं के विकास को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, बंगाली नाटक नील दर्पण (1860) में बताया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों का किस प्रकार शोषण किया जाता था।

आधुनिक रंगमंच सांस्कृतिक उत्पादन के औपनिवेशिक मॉडलों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रतिच्छेदन ने आधुनिक रंगमंच को आकार दिया है। रंगमंच सहित प्रदर्शन कलाएँ सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त साधन तथा चर्चा के लिए एक जीवंत मंच बनी हुई हैं। रंगमंच लंबे समय से भारत में जागरूकता बढ़ाने, सुधार और प्रतिरोध के लिए एक सशक्त साधन रहा है, जिसका प्रभाव राजनीतिक आंदोलनों के साथ-साथ सामाजिक संरचनाओं पर भी पड़ा है। शास्त्रीय रीति-रिवाजों से लेकर समकालीन नुकड़ नाटकों तक, इसने सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करने और प्रभावित करने के लिए कभी भी बदलाव करना बंद नहीं किया है। सामाजिक अन्याय को लंबे समय से रंगमंच के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण को 1860 में बंगाली थियेटर के नील दर्पण द्वारा सार्वजनिक किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर नाटकों और लोक प्रदर्शनों के माध्यम से संगठित किया गया था। रंगमंच के माध्यम से, भारतीय जन रंगमंच संघ (इप्टा) ने 1943 में उपनिवेशवाद विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। निम्न वर्ग के समुदाय रंगमंच के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करने में सक्षम रहे हैं। दलित सशक्तिकरण और अम्बेडकरवादी दर्शन को भीम नाट्य (महाराष्ट्र) द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। रंगमंच का उपयोग भ्रष्टाचार को उजागर करने और नीतियों की आलोचना करने के लिए किया गया है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।



इ | समें दो मत नहीं कि वर्तमान दौर में विशेष कर नई पीढ़ी का रझान सक्रिय राजनीति के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। वैसे भी निरंतर परिवर्तित दौर में ऐसा समझा जाता है कि पूर्व की तुलना में आजकल के नौनिहालों की सामान्य समझ एवं बुद्धि काफी हद कुशाग्र है। इसके चलते किशोर एवं युवा पीढ़ी भी निकट भविष्य में और अधिक प्रतिभा संपन्न होगी। अब वह समय नहीं रहा कि उम्र के आधार पर वरिष्ठता ही राजनीतिक योग्यता का निर्धारण करती रही हो। निश्चित ही नए दौर में देश प्रदेश की राजनीति में युवाओं की सक्रिय भागीदारी अब समय की मांग बन गई है। इस संदर्भ में विशेष रूप से भाजपा की राजनीतिक रणनीति की सराहना करनी चाहिए।

यू भी प्रगति के पैमानों का निर्धारण करने और उसे क्रिया रूप देने में जितने उत्साही युवा हो सकते हैं, उतनी अपेक्षा पुरानी पीढ़ी से तो नहीं की जा सकती। हालांकि उम्र की वरिष्ठता का भी अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन अनेक अवसरों पर ऐसा होता है कि देश प्रदेश के सर्वोगीण विकास हेतु कहीं-कहीं अनुभव से ज्यादा वर्तमान की समझ की बहुत अधिक मायने रखती है। यह निश्चित है कि पुरातन पंथी विचारधारा के चलते देश प्रदेश के प्रगति रथ को तीव्र गति प्रदान नहीं की जा सकती। दरअसल समय की धारा के अनुरूप अपनी विचारधारा को डालकर ही वर्तमान दौर में राजनीति के मूलभूत उद्देश्यों को पाया जा सकता है। एक प्रकार से अनुभव के साथ-साथ वर्तमान परिस्थितियों का

आर्थिकी

सचिन श्रीवास्तव

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।



भा | रतीय अर्थव्यवस्था इस समय गहरे संकट में है। सरकार के नीति-निर्माण में असंतुलन, कर्ज का बढ़ता बोझ और सरकारी संरक्षित पूंजीवाद के कारण प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। 80 प्रतिशत से अधिक जीडीपी के बराबर कर्ज और नीति निर्माण में बड़े कॉर्पोरेट समूहों की बढ़ती पकड़ ने देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरों में डाल दिया है। सरकार एक ओर निजीकरण और विनिवेश के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना चाहती है, जबकि दूसरी ओर कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों को बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। यह नीतियाँ न केवल आम जनता के लिए आर्थिक असुरक्षा पैदा कर रही हैं, बल्कि देश की प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी कमजोर कर रही हैं।

स्टेडिस्टा के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय कर्ज 2020 में 88.43 प्रतिशत जीडीपी तक पहुंच गया था, जो अब भी 80 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारी नीतियाँ कुछ विशेष औद्योगिक समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, न कि आम जनता या लघु-मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के हित में।

सरकारी बैंक और कंपनियाँ घाटे में बताकर बेची जा रही हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले उद्योगपतियों को सस्ते ऋण और टैक्स में छूट दी जा रही है। रेलवे, तेल कंपनियाँ, टेलीकॉम और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे को

सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े हैं कलाएं व रंगमंच

आधुनिक रंगमंच सांस्कृतिक उत्पादन के औपनिवेशिक मॉडलों और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रतिच्छेदन ने आधुनिक रंगमंच को आकार दिया है। रंगमंच सहित प्रदर्शन कलाएँ सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त साधन तथा चर्चा के लिए एक जीवंत मंच बनी हुई हैं। रंगमंच लंबे समय से भारत में जागरूकता बढ़ाने, सुधार और प्रतिरोध के लिए एक सशक्त साधन रहा है, जिसका प्रभाव राजनीतिक आंदोलनों के साथ-साथ सामाजिक संरचनाओं पर भी पड़ा है। शास्त्रीय रीति-रिवाजों से लेकर समकालीन नुकड़ नाटकों तक, इसने सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करने और प्रभावित करने के लिए कभी भी बदलाव करना बंद नहीं किया है। सामाजिक अन्याय को लंबे समय से रंगमंच के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता रहा है।



1980 के दशक में, सफ़दर हाशमी के जन नाट्य मंच ने नुकड़ नाटक प्रस्तुत किए जिनमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई; इसके कारण 1989 में उनकी हत्या कर दी गई। कानून और सामाजिक सुधार रंगमंच से प्रभावित हुए हैं। विजय तेंदुलकर की 1972 में प्रकाशित पुस्तक सखाराम बाईंडर में महिलाओं के अधिकारों और घरेलू दुर्व्यवहार के खुलासे पर चर्चा के परिणामस्वरूप सख्त सेंसरशिप कानून बनाये गये। धार्मिक और सामाजिक परंपराएँ:

प्राचीन रंगमंच की मज़बूत धार्मिक और सामाजिक जड़ें थीं। कुटियाट्टम (केरल), जिसे 2001 में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी, अभी भी संस्कृत रंगमंच की परंपराओं को कायम रखे हुए है। लोक रंगमंच के माध्यम से सामाजिक टिप्पणी- वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को लोक परंपराओं में प्रतिबिंबित किया गया है।

नक्सलवादी आंदोलन के दौरान वर्ग संघर्ष को जत्रा (बंगाल) में दर्शाया गया। आधुनिक रंगमंच में

मानवाधिकार, लोकतंत्र और भ्रष्टाचार नए विषय बन गए। 1950 के दशक में हबीब तनवीर के नया थिएटर ने लोक और आधुनिक विषयों को मिलाकर सामाजिक मुद्दों को चित्रित किया। राज्य हस्तक्षेप और सेंसरशिप: राजनीतिक रूप से संवेदनशील नाटकों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। विजय तेंदुलकर की 1972 की फ़िल्म घासीराम कोतवाल की जाति आधारित भ्रष्टाचार और शोषण को उजागर करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता ने थिएटर के प्रभाव और पहुंच को बढ़ा दिया है। सामाजिक सक्रियता के लिए, यूट्यूब आधारित थिएटर समूह, जैसे जन नाट्य मंच, डिजिटल प्रदर्शनों का उपयोग करते हैं। भारत और विदेश के सरकारी और निजी स्रोतों ने स्वतंत्रता के बाद से भारतीय रंगमंच को इसके अनेक रूपों में सहयोग दिया है, लेकिन यह हमेशा विशिष्ट प्रतिभाओं द्वारा संचालित रहा है और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित रहा है, साथ ही स्वदेशी संसाधनों की ओर भी मुड़ता रहा है। इस अवधि के दौरान विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश और गिरिश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबार, पी लंकेश और इंदिरा पार्थसारथी जैसे आधुनिकतावादी नाटककार पैदा हुए; उनके नाटकों का उपयोग और अध्ययन पूरी दुनिया में किया गया है।

इन नाटककारों ने थिएटर में आधुनिकतावादी आक्रोश पर गहन औपचारिक कठोरता और विषयगत ध्यान केंद्रित किया। पहचान का संकट और वैश्वीकरण के परिणाम उन विषयों में से हैं जिन पर युवा लेखक वर्तमान में कई स्थानों पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय रंगमंच मुख्यतः तीन परंपराओं से प्रभावित है: संस्कृत रंगमंच, लोक रंगमंच और पश्चिमी रंगमंच। वास्तव में, तीसरा वह है जिसे आज

भारतीय रंगमंच की आधारशिला माना जा सकता है। हम सभी देख सकते हैं कि समय के साथ रंगमंच और प्रदर्शन कलाएँ किस प्रकार विकसित हुई हैं, उन्होंने सत्ता को चुनौती दी है, न्याय को बढ़ावा दिया है, तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है। आज, पूरे देश में कई थिएटर समूह और निजी से लेकर सरकारी संस्थानों तक कई थिएटर अभिनय संस्थान हैं। अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, उन्हें सांस्कृतिक संरक्षण, डिजिटल एकीकरण और नीति समर्थन के लिए पहले के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। जबकि शोषितों या आम जनता के जीवन में सामाजिक परिवर्तन लाना, नुकड़ नाटक आंदोलन और यात्रा के केंद्र में है।

इसे प्राप्त करने के लिए ‘प्रगतिशील सामुदायिक विकास’ प्रक्रिया को ‘लोकप्रिय शिक्षा’ के साथ संयोजित करना आवश्यक है। एक लोकप्रिय रंगमंचीय अभ्यास के रूप में, नुकड़ नाटक एक सहभागी प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो लक्षित दर्शकों के ‘सांस्कृतिक रूपों’ के प्रति संवेदनशील होती है। नुकड़ नाटक, प्रोसेनियम थिएटर के विपरीत, वह स्थान है जहाँ अभिनेता अपनी कलात्मक और व्यावसायिक रुचियों को अपनी राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं के साथ जोड़ते हैं। हालाँकि, इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने और समाज पर प्रभाव डालने के लिए दीर्घकालिक विकासात्मक योजना को नाट्य प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह लक्ष्य नुकड़ नाटक के माध्यम से समुदाय को जानने, लोगों की चिंताओं के मुद्दों को पहचानने, मनोरंजन और सामुदायिक अभिव्यक्ति को संयोजित करने, दर्शकों की भागीदारी को आमंत्रित करने और कार्यवाही के लिए आह्वान करने से प्राप्त किया जा सकता है।

युवाओं के प्रति भाजपा का विश्वास सुखद अनुभूति का कारक

ज्ञान भी बहुत मायने रखता है।

इस संदर्भ में भाजपा ने अपने शासनकाल में अनेक अवसरों पर चौंकाने वाले निर्णय लेकर जमीनी कार्यकर्ता तथा नेताओं को उत्साह से लबरेज कर दिया है। कल तक यह समझा जाता था कि पारिवारिक दृष्टि से बिना किसी ठोस राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेतृत्व की कमान हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन बीते समय में भाजपा शासित राज्यों में द्वितीय एवं तृतीय पॉक्त के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की कमान सौंप कर भाजपा ने वंशवाद के दंश का काफी हद तक समुचित उपचार कर दिया था। हाल ही में नई दिल्ली की कमान पहली बार की विधायक को सौंपा जाना भी इस बात का द्योतक है कि समर्पित कार्यकर्ताओं के कार्य का भाजपा द्वारा समुचित संज्ञान लिया जाता है।

वैसे तो यह भाजपा की अंदरूनी रीति नीति का मुद्दा है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव देश प्रदेश की राजनीति पर पड़े बिना नहीं रहेंगे। वर्तमान दौर में अधिकांश प्रतिपक्षी दलों पर व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक नियंत्रण है। अधिकांश दलों में विचारधारा से अधिक व्यक्तिगत मनमर्जी का बोलबाला है। अपनों को उपकृत करते हुए अपने-अपने गुट एवं समूह को ताकतवर बनाने के निरंतर प्रयास होते रहा करते हैं। अधिकांश प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते राजनीति के मैदान में डटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त जनाधार रहित नेताओं की भी भरमार है। एक प्रकार से इस वर्ग के पास अपने दल की राजनीति का एक अलग ही रिमोट कंट्रोल हुआ करता है।



निश्चित ही भाजपा को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने अपनी कार्य पद्धति से देश- प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की है। आज स्थिति यह है कि अन्य दलों की अपेक्षा भाजपा के पास निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता तथा जनसेवा की भावना से ओतप्रोत छोटे-बड़े नेताओं की एक बड़ी फौज है। हर कोई इस विश्वास से भरा हुआ है कि दल के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण की भावना उसे बहुत आगे तक ले जा सकती है। क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वह अपना काम कर रहे हैं, तो दल द्वारा उसका संज्ञान भी लिया जाता है। यही कारण है कि भाजपा

लगभग शून्य से शिखर तक का सफर कर सकी है।

हालांकि कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा जा सकता है, कमियाँ निकाली जा सकती है, सत्ता संस्कृति को आत्मसात करने का आरोप भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि बाकी की तुलना में भाजपा की बात ही कुछ और है। वैसे यह विश्वास केवल कार्यकर्ता को ही नहीं है, अपितु आम नागरिक भी भलीभाँति जानने लगे हैं कि भाजपा के राज में उनका कभी सामंत्तशाही से पाला नहीं पड़ा। यह खानदान की नहीं कार्यकर्ताओं की पाटी है। यही बात इसे औरों से अलग करती है। राजनीति का मैदान हर किसी के लिए खुला है। लेकिन जिनके अंतर्मन में दृढ़ता होती है और नीति तथा सिद्धांतों के प्रति समर्पण की भावना होती है, उनके लिए भाजपा ही वह विकल्प है जहाँ संकल्प पूरे हो सकते हैं।

वर्तमान में देश और अनेक प्रदेशों का नेतृत्व वह शख्सियत कर रही है - जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी राजनीतिक नहीं रही। एक प्रकार से सभी ने साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही राजनीतिक सफर पूर्ण किया। परिणामस्वरूप सिद्धि (सत्ता) प्राप्त होने पर योग्यता के अनुसार ही सभी के हिस्से में अपना-अपना काम आया। अब यह अलग बात है कि भाजपा के विरोधी भाजपा का विरोध तो करेंगे ही। उनका ऐसा विरोध करना ही उन्हें राजनीतिक दृष्टि से मैदान में बनाए रखता है। लेकिन आम नागरिक तब और अब में अंतर महसूस करने लगे हैं। यही कारण है कि भाजपा की प्रभावशीलता में निरंतर वृद्धि होने लगी है। जबकि प्रतिपक्षी दल सही तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन भी नहीं कर पा रहे हैं।

वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का संकल्प

कुछ खास समूहों के हाथों बेचा जा रहा है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। छोटे व्यापारियों और किसानों को बाजार के भरोंसे छोड़ दिया गया, जबकि बड़े उद्योगपतियों को अरबों की टैक्स रियायतें दी जा रही हैं। सरकार बार-बार कहती है कि सार्वजनिक उक्रम घाटे में हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बीपीसीएल, एलआईसी, रेलवे, सेल और अन्य कंपनियों को या तो बेचा जा रहा है या उनके संसाधन निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो पैसा आ रहा है, वह मौजूदा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि नए कॉर्पोरेट टैक्स छूट और सरकारी खर्च बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा है। बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है, क्योंकि सरकारी संरक्षण प्राप्त निजी कंपनियाँ मनमाने दाम वसूल रही हैं। सवाल वही है कि यह निजीकरण की नीति है या बस बड़े कॉर्पोरेट समूहों को फायदा पहुंचाने का तरीका?

तीन कृषि कानूनों को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश सरकार की नवउदारवादी सोच और पूंजीपतियों की लॉबी का स्पष्ट प्रमाण थी। ये कानून किसान आंदोलन के दबाव में वापस लिए गए, लेकिन सरकार अब भी कृषि सेक्टर में बड़े उद्योगपतियों को प्रवेश दिलाने की कोशिश कर रही है। एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जा रही, ताकि किसान मजबूरी में निजी कंपनियों को अपनी उपज बेचें। कृषि को ठेकेदारी खेती के हवाले करने की योजनाएँ अब भी जारी हैं, जिससे छोटे किसान बिचौलियों और बड़ी कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। सरकार ने एफसीआई का बजट लगातार घटाया है, जिससे सरकारी खरीद कमजोर हुई और किसान खुले बाजार में जाने को मजबूर हुए।

किसान विरोधी नीतियाँ क्यों खतरनाक हैं?



- खाद्य सुरक्षा पर खतरा:** अगर कृषि उत्पादन पूरी तरह बाजार के हाथ में आ गया, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें निजी कंपनियाँ तय करेंगी, जिससे गरीबों के लिए अनाज महंगा हो जाएगा।
- छोटे किसानों की बर्बादी:** भारत में 86 प्रतिशत से अधिक किसान लघु या सीमांत श्रेणी के हैं। बड़े कॉर्पोरेट के साथ प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाएंगे।
- भूमि अधिग्रहण और विस्थापन:** कॉर्पोरेट खेती के बढ़ने से गाँवों में जमीनें उद्योगपतियों के हाथों में जाएँगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर सरकार सच में किसानों का भला चाहती है, तो उसे एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी। एफसीआई को मजबूत करना होगा, ताकि सरकारी खरीद में कोई गिरावट न हो। कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना

होगा, जिससे किसान आत्मनिर्भर बनें।

प्रतिस्पर्धा बाजार को कमजोर करने की साजिश सच्चे प्रतिस्पर्धी बाजार का अर्थ है कि कोई भी नया व्यवसायी बिना किसी भेदभाव के बाजार में प्रवेश कर सके और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले। लेकिन भारत में सरकार खुद ही कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को बाजार पर कब्जा करने में मदद कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ दो-तीन कंपनियाँ ही बची हैं, क्योंकि अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया। एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे, बिजली उत्पादन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बैंकों से कर्ज माफ़ी और टैक्स छूट केवल कुछ बड़े व्यापारिक समूहों को दी जाती है, जबकि छोटे व्यापारियों को लोन भी नहीं मिलता।

इसका खतरा क्या है?

- महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कम प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियाँ मनमाने दाम वसूलेंगी।
- नए बिज़नेस शुरू करना मुश्किल होगा, क्योंकि नए व्यवसायियों को बड़े कॉर्पोरेट के साथ मुकाबला करना असंभव होगा।
- रोजगार कम होंगे, क्योंकि बड़े औद्योगिक समूह मशीनों और स्वचालन (ऑटोमेशन) पर निर्भर रहेंगे, जिससे नौकरियाँ घटेगी।

सरकार अगर सच में मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा चाहती है, तो उसे छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी समान अवसर देने होंगे। एकाधिकारवाद को खत्म करने के लिए नियम और कानून सख्त करने होंगे। सरकारी बैंकों को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए इस्तेमाल करने की नीति बंद करनी होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, लेकिन इस संकट का कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारी नीतियाँ और कॉर्पोरेट संरक्षणवाद है। सरकार जिन सुधारों की बात कर रही है, वे वास्तव में सिर्फ कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। निजीकरण का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सार्वजनिक संसाधनों की लूट है। कृषि क्षेत्र में बड़े कॉर्पोरेट्स को सुस्पैट को रोकना जाना चाहिए, ताकि किसान बिचौलियों का शिकार न बनें। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली सरकारी रियायतों को खत्म किया जाना चाहिए।

आज सवाल यह नहीं है कि भारत आर्थिक संकट से बाहर कैसे निकलेगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या सरकार सच में आम जनता की भलाई चाहती है, या सिर्फ अपने प्रिय उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहती है?



केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर ने नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु विभाग में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी से केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को अवगत कराया।

प्रदेश में बनेगी साइंस सिटी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में साइंस सिटी विकसित की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है। विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग कर प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों से जुड़ी व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। इसमें ड्रोन सर्वे, फसल सर्वे के कार्य शामिल है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों सहित जनसामान्य की रूचि और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान गतिविधियों का विस्तार संभाग स्तर तक किया जाएगा। आने वाले समय में मध्यप्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में सम्पन्न और समृद्ध बनें इस उद्देश्य से राज्य सरकार नवाचारों तथा अन्य गतिविधियों को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार विज्ञान भवन में मीडिया से चर्चा में व्यक्त किए।

राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान 3 मार्च को मंत्रालय के सरदार पटेल पार्क में अब प्रात : 10 बजे से

भोपाल (नप्र)। मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत ‘वन्देमातरम’ एवं राष्ट्र-गान ‘जन- गण-मन’ का गायन 3 मार्च को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। पूर्व में यह गायन प्रातः 11 बजे होता था। अब समय परिवर्तित कर प्रातः 10 बजे किया गया है। 1 एवं 2 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण राष्ट्र-गीत एवं राष्ट्र-गान का आयोजन 3 मार्च का किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्र-गीत एवं राष्ट्र-गान का आयोजन सरदार पटेल पार्क में किया जाता है।

मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को सुविधा

बरागवां स्टेशन पर रुकने वाली इन 8 ट्रेनों की अवधि को बढ़ाया

भोपाल (नप्र)। यात्रियों की सुविधा को स्थान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली आठ ट्रेनों के बरागवां स्टेशन पर ठहराव की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 1 मार्च 2025 से अगले आदेश तक प्रायोगिक रूप से लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और यात्रा से पहले रेलवे स्टेशन, रेल मद्दद सेवा 139 या हज़रक्षर ऑनलाइन पोर्टल से अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

इस फैसले के तहत अहमदाबाद-कोलकाता, कोलकाता-मदार जंक्शन, संतरागाछी-अजमेर और हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस सहित आठ ट्रेनों के ठहराव का समय संशोधित किया गया है।

संशोधित ठहराव समय

ट्रेन संख्या और नाम	आगमन	प्रस्थान
19413 (अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20
19414 (कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
19607 (कोलकाता-मदार जंक्शन एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
19608 (मदार जंक्शन-कोलकाता एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20
18009 (संतरागाछी-अजमेर एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
18010 (अजमेर-संतरागाछी एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20
13025 (हावड़ा-भोपाल एक्सप्रेस)	सुबह 05:33	सुबह 05:35
13026 (भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस)	रात 20:18	रात 20:20

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले संशोधित समय सारणी की पुष्टि कर लें, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

पैक्स कर्मचारी उग्र आंदोलन की राह पर

सीहोर (नप्र)। साठ फीसदी पदों पर मौजूदा कर्मचारियों की भर्ती और नियमित वेतनमान को लेकर सहकारिता विभाग के पैक्स कर्मचारी एक बार फिर उग्र आंदोलन की तैयारी में है। पैक्स कर्मचारी 5 मार्च को मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री और विध्याचल भवन का घेराव कर सकते हैं । पैक्स कर्मचारी जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि अंतिम प्रयास मुख्यमंत्री और विभाग मंत्री से मुलाकात करना है। इसके बाद कर्मचारी आगे की रणनीति बनाने के लिए निरंतर अप्रत्यक्ष तौर पर बैठक कर रहे हैं। कर्मचारियों ने पीड़ा बताई है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच जोखिम उठाकर कम किया। सरकार के हर आदेश का पालन करते हुए गरीब जनता और किसानों



की सेवा की। इस दौरान कई को जान भी गई। उसके बाद भी पीओएस मशीन में उक्त खाद्यान्न को कम नहीं किया गया। आरोप है कि सरकार ने मांगों के निराकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि वर्ष 2023 में सरकार से जो समझौता हुआ था। उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। सरकार में विभाग अधिकारियों और मंत्रियों के बीच 60 फीसदी भर्ती का भी समझौता हुआ था। उसका भी पालन नहीं किया गया है। जबकि पैक्स संस्थाओं के कर्मचारी नियमित पदों पर काम करने की प्रतीक्षा में रियायत हो रहे हैं। पूर्व सरकार ने दो बार तिथि तय की। लेकिन उनकी महापंचायत नहीं बुलाई गई। इन तमाम समस्याओं को लेकर अब आंदोलन करना ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है।

जीआईएस-भोपाल ने किया मध्यप्रदेश में सड़क अवसंरचना के नये युग का सूत्रपात : मुख्यमंत्री

1 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक एमओयू से प्रगति का मार्ग होगा प्रशस्त

है। इनमें इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर, भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज-जबलपुर-नागपुर कॉरिडोर, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेसवे, आगरा-व्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड



(पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और व्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास शामिल है।

नवीन सड़क परियोजनाएं न केवल मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से जोड़ेंगी, बल्कि राज्य के प्रमुख शहरों को भी आपस में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इससे यात्रा का समय घटेगा, लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन की लागत कम होगी, तथा कृषि, उद्योग, पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों को नए अवसर मिलेंगे।

42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप

भोपाल के बड़े तालाब पर होगा 25 राज्यों की रोइंग टीमों का महामुकाबला

3 से 7 मार्च तक होगा आयोजन, मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे शुभारंभ,मंत्री सारंग ने की तैयारियों की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों और कोच के ठहरने, भोजन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही, प्रतियोगिता का सजीव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बोट क्लब सहित शहर के प्रमुख चौराहों पर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक खेल प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकें। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एल. यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 3 से 7 मार्च तक 25 राज्यों के 500 खिलाड़ी **होगे शामिल**-मंत्री श्री सारंग ने बताया कि बड़े तालाब स्थित मध्यप्रदेश राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब पर 3 मार्च से 7 मार्च तक 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ.



मोहन यादव 3 मार्च को प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ी रोइंग, ब्याकिंग-केनोइंग, सेलिंग और स्लालम खेलों की विशेष प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर खेल प्रेमियों को जल क्रीड़ा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि चैंपियनशिप में 25 राज्यों से लगभग 500 प्रतिभागी भाग लेंगे। जिसमें रोइंग के कुल 14 इवेंट होंगे। यह चैंपियनशिप देश के शीर्ष रोवर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी। **इन कैटेगरी में होंगी प्रतियोगिताएं**—42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष, सीनियर महिला और

सिविलियन), काइपल स्कल्स (M4X) और कॉक्स्ड ईंट्स (M3+) शामिल हैं।

सीनियर महिला वर्ग में सिंगल स्कल्स (W1X), डबल स्कल्स (W2X), कॉक्सलेस पेयर्स (W2-), कॉक्सलेस फोर्स (W4-), लाइटवेट वुमन डबल स्कल्स (LW2X), काइपल स्कल्स (W4X) और कॉक्स्ड ईंट्स (W8+) की स्पर्धाएं होंगी। पैरा रोइंग स्पर्धाओं में पैरा मेन सिंगल स्कल (PR३M1X) और पैरा वुमन सिंगल स्कल (PR३W1X) प्रतियोगिताएं होंगी।

रीवा में बहू की हत्या में ससुर गवाही ना दे, इसलिए उसे ही मार डाला...

रीवा (नप्र)। मनगवां थाना क्षेत्र के मंनिकावार गांव में जनपथ हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना में उस वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जो कि अपने ही बेटे और बहू पर प्राणघातक हमले का गवाह रहा।

उस घटना में वृद्ध की बहू की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि इस घटना के आरोपित चाहते थे कि वृद्ध ससुर न्यायालय में वो गवाही न दे, लेकिन वो पीछे हटने तैयार नहीं रहा। इसी रंजिश के चलते गुरुवार की देर रात ससुर की भी हत्या कर दी गई।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डेटा स्टोरेज सटीकता बढ़ाने के लिए विकसित की सेमीकंडक्टर चिप

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तकनीकी शिक्षा में निरंतर स्थापित हो रहे नए आयाम : मंत्री परमार

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आरुप्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिवार को, सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने की नवाचारी शोध करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं। मंत्री श्री परमार ने शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. वैभव नीमा एवं उनके सहयोगी शोधार्थियों के पुरुषार्थ से सृजित यह नवाचार, तकनीक के क्षेत्र में निश्चित ही अपनी महती उपयोगिता सुनिश्चित करेगा। श्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के यशस्वी नेतृत्व में, राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और इसमें नवाचार, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं प्रगति के साथ, शैक्षणिक एवं अकादमिक स्तर पर उत्तरोत्तर गुणवत्ता वृद्धि हो रही है। श्री परमार ने कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने नवाचारी शोध के लिए विश्वविद्यालय परिवार को दी शुभकामनाएं

ना, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी शोध करना, प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। प्रदेश के समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थान भी शोध एवं नवाचार की दिशा में, नवीन आयाम स्थापित करने के लिए प्रयास करें।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) इंदौर ने एक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन की है, जो डेटा स्टोरेज की सटीकता को बढ़ाती है, जिससे सैटेलाइट इमेजरी और बायोमेडिकल एप्लीकेशन को फायदा होता है। सेमीकंडक्टर चिप को डीएवीवी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के वीएलएसआई ग्रुप द्वारा टाइनी टेपआउट शैक्षणिक परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह परियोजना सेमीकंडक्टर डिजाइन को अधिक सुलभ और किफायती बनाने का लक्ष्य रखती है। इस उपलब्धि के साथ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय उन प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक फैब्रिकेटेड सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन किया है।

सेमीकंडक्टर चिप का विकास

और विशेषताएँ—यह चिप स्काईवाटर की 130एनएम तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो डेटा त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उन्हें सुधार सकती है। यह सफलता देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करती है और विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है।

शोधार्थी टीम और अनुसंधान प्रक्रिया—देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी के फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स समेत सात सदस्यों की टीम ने इस चिप को डिज़ाइन किया है और इसे फैब्रैब मिलेशिया से फैब्रिकेट करवाया है। इस टीम का नेतृत्व डॉ. वैभव नीमा ने किया, उनके साथ प्रोफेसर रवि सिंदल, सुश्री प्रियंका शर्मा, श्री आशीष पंचाल और पीएचडी स्कॉलर्स श्री ऋषभ बडजातिया, श्री अमित साहनी और सुश्री आस्था गुप्ता शामिल हैं। शोधार्थी टीम ने पिछले लगभग डेढ़ साल से इस सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइन करने की दिशा में समर्पित परिश्रम किया। आईईटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शैलेश सिंह चौहान ने भी इस परियोजना में



कुक्षी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक 135 किमी चलेगा कूज

एमपी में 100 करोड़ का निवेश प्रस्ताव; इलेक्ट्रिक-सोलर के होंगे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में कूज प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अयोध्या कूज लाइन्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीएसआई) में प्रस्ताव दिया है। ऐसे में 135 किमी लंबे कुक्षी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी समेत 6 में से किसी एक रुट पर कूज पानी की लहरों पर दौड़ने लगेगा। वहीं, 70 करोड़ रुपए का निश श वाटर एक्टिविटी पर भी किया जाएगा। खास बात ये है कि कूज इलेक्ट्रिक या सोलर से ही चलेंगे। डीजल इंजन वाले कूज-मोटर बोट्स पर एमपी में रोक लगाई है। जिस कंपनी ने एमपी में कूज चलाने का प्रस्ताव दिया है, उसके अभी सरयू नदी पर 2 कूज चल रहे हैं। वहीं, उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जनपद में गंगा नदी के बृज घाट से राम घाट तक 2 कूज, हाउस बोट्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने वाली है।

3 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देकर किया कौशल उन्नयन

2383 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में इस वर्ष शुरु की गई व्यावसायिक शिक्षा

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के लिये इस वर्ष 3 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाई गई है। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 2383 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की गई है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों को सुलभता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिये व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि तेजी से बढ़ती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था में हम सभी का किस प्रकार से योगदान हो। बढ़ती हुई आबादी के साथ जनता के लिये उनकी शिक्षा, कौशल तथा आकांक्षाओं के

सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एसओसी सिस्टम डिजाइन को स्नातक, मास्टरस और अनुसंधान स्तर पर सीखने में सहायता मिलेगी।

यह भारत में फैबलेस डिज़ाइन स्टार्टअप के विकास को भी बढ़ावा देगा।

चिप के लाभ और भविष्य की योजनाएँ—डॉ. वैभव नीमा ने बताया कि इस चिप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह डेटा सटीकता सुनिश्चित कर सकती है, जो सैटेलाइट इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च और एआई-आधारित एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में सटीक डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है।

इसकी स्वतः त्रुटि पहचान और सुधार तकनीक से डेटा के खराब होने के जोखिम को कम करती है। अगले चरण में, वीएलएसआई टीम चिप का परीक्षण और स्थापन करेगी। एक बार चिप को मान्यता मिलने के बाद इसे, चिप को औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पेश किया जाएगा, जो संभवतः स्वास्थ्य सेवा और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा। आईटी, वीएलएसआई टीम अगले वर्ष तक दो और परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बना रही है।

